



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ 1939 (श0)

(सं0 पटना 605) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 जून 2017

सं0 22/नि0सि0(सम0)-02-07/12-863—श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध उक्त प्रमण्डलान्तर्गत एम0आर0 फंड से कराये गये सम्पोषण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत निम्न आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-1429, दिनांक 25.09.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया :-

(1) दिनांक 31.3.12 तक कार्य समाप्त नहीं होने के बावजूद भी सम्पूर्ण राशि का भुगतान दिनांक 30.3.12 के पूर्व ही कर दिया गया जो वित्तीय अनियमितता एवं गलत मंशा को परिलक्षित करता है।

(2) विभागीय पत्रांक 28/28-7-30-82/2000-171 दिनांक 27.7.2000 में निहित निदेशों में उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कराये गये कार्यों का भुगतान मापपुस्त में विपत्र के रूप में बिल तैयार कर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है। यहाँ तक कि मापपुस्त से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि भुगतान किस श्रमिक तथा किस आपूर्तिकर्ता को किया है। फलतः वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिए आप दोषी हैं।

(3) स्वीकृत प्राक्कलित राशि के समतुल्य ही भुगतान किया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि बिना Contractor Profit धटाये ही भुगतान किया गया है, जबकि सभी कार्य विभागीय रूप से कराया गया है। फलतः यह अधिकायी भुगतान का मामला है, जिसके लिए आप दोषी हैं।

(4) कार्यों में न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने के लिए भी आप दोषी पाये गये हैं।

श्री प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत आरोप सं0-1 एवं 3 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप सं0-02 जो विभागीय पत्रांक-28/28-7-30-82/2000-171, दिनांक 27.07.2000 में निहित निर्देशों का उल्लंघन कर बिना श्रमशक्ति स्वीकृत कराये ही मास्टर रौल पर भुगतान न कर विपत्र के रूप में भुगतान करने तथा सामग्री आपूर्ति के भुगतान अनियमित ढंग से करने से संबंधित है, के संबंध में श्री प्रसाद ने अपने बचाव बयान में उल्लेख किया है कि अल्प अवधि में विभागीय रूप से कार्य कराने हेतु भारी संख्या में मजदूरों को जुटा पाना संभव नहीं हो पाने के कारण मजदूर मेट से कार्य कराने हेतु भारी संख्या में मजदूरों को जुटा पाना संभव नहीं हो पाने के कारण मजदूर मेट के माध्यम से श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कार्य कराया गया तथा मेट के माध्यम से प्राप्त

प्रमाणक को पारित करते हुए श्रमिकों को वास्तविक भुगतान किया गया है, निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणक को विधिवत पारित कर भुगतान किया गया है।

श्री प्रसाद से आरोप सं०-02 के संबंध में प्राप्त जवाब की समीक्षा में पाया गया कि मापपुस्त सं०-1192,1185, 1187, 1189, 1190,1191, 1193, 1194, एवं 1208 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य में संलग्न श्रमिकों का भुगतान विभिन्न मेटो के माध्यम से प्राप्त प्रमाणक को पारित करते हुए भुगतान किया गया है तथा सामग्री की आपूर्ति का भुगतान आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणक को पारित कर किया गया है जबकि विभागीय पत्रांक-28/28-7-30-82/2000-171, दिनांक 27.7.2000 के अनुसार श्रमिकों का भुगतान सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित श्रमबल के आधार पर मास्टर रोल के माध्यम से किया जाना है तथा सामग्री की खरीद आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति के बाद उनसे प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया जाना है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री की आपूर्ति का भुगतान आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रमाणकों को पारित कर किया गया परंतु उक्त निदेशों का उल्लंघन करते हुए श्रमिकों का सक्षम अधिकार से न तो श्रमशक्ति की स्वीकृति प्राप्त की गयी है एवं न ही मास्टर रोल पर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्य में वास्तविक रूप से संलग्न श्रमिकों का भुगतान हुआ है अथवा नहीं। अतः श्री अहमद के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-171, दिनांक 27.7.2000 में निहित निदेशों का उल्लंघन कर श्रमिकों के भुगतान करने की कार्यवाई का आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-4 जो न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने से संबंधि है के संबंध में श्री अहमद के बचाव बयान में उल्लेखित है कि कार्य में चहारदिवारी के Dismantle में प्राप्त Salvage Brick (पुराना ईट) तथा आवश्यकतानुसार नये ईट की आपूर्ति लेते हुए कार्य कराना था तथा salvage से प्राप्त ईट तथा आवश्यकतानुसार नये ईट की आपूर्ति लेकर कार्य कराया गया है। उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा नमूना संग्रह में नये एवं पुराने ईटों का नमूने संग्रह किये गये हैं। चूँकि दीवार तोड़कर पुराने ईट का संग्रहण के क्रम में तोड़ने, ढोने तथा स्टैक करने के क्रम में इन ईटों में हेयर क्रैक होना तथा कालांतर में इसके compressive strength में कमी पाया जाना स्वभाविक है।

प्राप्त जवाब की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जाँच फल से स्पष्ट है कि तीन नमूनों में से दो अदद नमूनों का औसत compressive strength $(124.73+88.87)/2=106.80\text{kg/cm}^2$ पाया गया है। (46.77kg/cm^2) जबकि एक अदद ईट का compressive strength मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि जाँच दल द्वारा स्थल से संग्रहित तीन अदद ईट का नमूना नये आपूर्ति का है अथवा ईट (पुराना ईट) का जबकि site A/c Book के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्य में salvage से कुल 24830 अदद ईट प्राप्त कर कार्य में उपयोग किया गया परिलक्षित होता है। उड़नदस्ता द्वारा तीन अदद ईट का नमूना संग्रह कर सिंचाई शोध संस्थान, खगौल, पटना से जाँच करायी गयी है। जाँच में ईट का compressive strength 88.87kg/cm^2 , 46.77kg/cm^2 एवं 124.73kg/cm^2 पाया गया है। ईट का compressive strength 46.77kg/cm^2 पाया जाना परिलक्षित करता है कि या तो ईट बहुत ही खराब विशिष्टि का है अथवा पुराना ईट हो सकता है। चूँकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि नमूना संग्रह में पुराना ईट लायी गयी है। साथ ही बचाव बयान में यह तथ्य कि नमूना संग्रह में पुराना ईट था, प्रमाणित नहीं होता है। बचाव बयान में भी पुराना ईट होना मात्र संभावना के रूप में है। ऐसी स्थिति में उक्त ईट के नमूने को पुराना ईट माना जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतएव तीनों ईटों का औसत compressive strength $(124.73+88.87+46.77)/3 = 86.79\text{kg/cm}^2$ होता है जो मानक के अनुरूप नहीं है। अतः न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप सं०-02 विभागीय पत्रांक-28/28-7-30-82/2000-171 दिनांक 27.07.2000 में निहित निदेशों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकार से बिना श्रमशक्ति की स्वीकृति कराये एवं मास्टर रोल पर श्रमिकों का भुगतान न कर मेट के माध्यम से भुगतान करने के प्रक्रियात्मक त्रुटि तथा आरोप सं०-4 कार्य में न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा को विभागीय अधिसूचना संख्या-733, दिनांक 26.03.2015 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री नागेश्वर प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित बातें कही गयी :-

(i) अल्पावधि में विभागीय रूप से कार्य कराने हेतु भारी संख्या में मजदूरों को जुटा पाना संभव नहीं हो पाने के कारण मजदूर मेट के माध्यम से श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कार्य कराया गया तथा मेट के माध्यम से प्राप्त प्रमाणक को पारित कर श्रमिकों को वास्तविक भुगतान किया गया।

(ii) जाँच दल द्वारा मापपुस्त में दर्ज मात्रा स्थल पर सम्पादित कार्य के अनुरूप पायी गयी। अतः इस संदर्भ में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी। स्पष्ट है कि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गयी।

(iii) विभागीय पत्रांक 171, दिनांक 27.07.2000 में निहित निदेशों के संबंध में कहा गया है कि विभागीय स्तर से प्रस्तावित/संपादित सारे कार्य के लिए आवश्यक श्रम शक्ति का आकलन करते हुए प्रस्ताव संबंधित अंचलीय

कार्यालय को उपलब्ध कराया गया ताकि श्रम शक्ति का अनुमोदन ससमय सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जा सके (साक्ष्य संलग्न)। वित्तीय वर्ष 2011-12 समाप्ति के कगार पर रहने तथा सक्षम प्राधिकार से श्रमशक्ति का अनुमोदन अप्राप्त रहने के कारण एवं अत्यंत ही बड़ी राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पूर्व होना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता के मौखिक निदेश के अनुपालन में मापपुस्त पर विपत्र के रूप प्रविष्टि कर प्रमंडलीय कार्यालय को पारित हेतु भेजा गया। विपत्र पारित किये जाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कार्यपालक अभियंता भी वस्तुस्थिति से अवगत थे। अधोहस्ताक्षरी के उक्त कृत से मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि माना जा सकता है। क्योंकि इसमें सरकारी राशि की न हानि हुई है न ही अपव्यय हुआ है।

(iv) जाँचित ईट के नमूनों में पुराना एवं नये ईट के नमूना लिया गया था। सभी नमूनों का water absorption मानक के अनुरूप पाये जाने से स्पष्ट होता है कि न्यून विशिष्टि के ईटों का व्यवहार कार्य में नहीं किया गया था एवं नये ईटों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रहने के फलस्वरूप उसका compressive strength मानक के अनुरूप पाया गया जबकि पुराने ईट (salvage brick) का compressive strength मानक से काफी कम पाया गया है। ईट के compressive strength में अप्रत्याशित कमी इसे तोड़ने के क्रम में Havelin fracture उत्पन्न हो जाने के कारण स्वभाविक है। जाँच की गयी ईटों का water absorption 20% से कम पाये जाने के कारण इन ईटों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में वर्णित तथ्यों की विभागीय समीक्षा की गयी जिसमें निम्न तथ्य पाया गया :-

(i) आरोपी द्वारा प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप यथा बिना सक्षम प्राधिकार से श्रमशक्ति की स्वीकृति कराये एवं बिना मास्टर रौल के संधारण किये ही भुगतान के संदर्भ में वही तथ्य अपने पुनर्विलोकन अर्जी में कहा गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में कहा गया था यथा माह मार्च 2012, के समाप्ति के कगार पर रहने के कारण श्रमशक्ति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राप्त अग्रिम के समायोजन हेतु श्रमिकों का भुगतान मेट के माध्यम से किया गया है। जिसे स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि विभागीय पत्रांक 171, दिनांक 20.07.2000 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी परिस्थिति में हैण्ड रिसीट द्वारा भुगतान करने की स्पष्ट मनाही है। मजदूरों सिर्फ मास्टर रौल पर ही किया जाना है इसके लिए प्राक्कलन तथा श्रमबल सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना है जबकि आलोच्य कार्य में न तो सक्षम प्राधिकार से श्रमबल की स्वीकृति ही करायी गयी है न ही मास्टर रौल का संधारण ही किया गया है। उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यों का भुगतान विपत्र तैयार कर की गयी है।

(ii) कार्य में न्यून विशिष्टि के ईट के उपयोग होने के संदर्भ में आरोपी अपने पुनर्विलोकन अर्जी में पूर्व के स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्य को दुहराया गया है। इनके द्वारा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है उक्त के आलोक में न्यून विशिष्टि के ईट के उपयोग होने के संदर्भ में दिये गये तथ्य को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा के आलोक में श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा का पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार योग्य मानते हुए दोनों आरोप तथा विभागीय पत्रांक-171, दिनांक 27.07.2000 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना सक्षम प्राधिकार से श्रमशक्ति की स्वीकृति प्राप्त किये बिना मास्टर रौल संधारण किये ही अनियमित ढंग से भुगतान की कार्यवाई करने तथा कार्य में न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने के आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा के आधार पर श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए अधिरोपित दण्ड "दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" को बरकरार रखते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-733, दिनांक 26.03.2015 द्वारा अधिसूचित दण्ड को बरकरार रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 605-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>